नईदुनिया

मातृशक्ति उत्तराखंड की असली ताकत सशक्त नारी से बनेगा समृद्ध प्रदेशः धामी

नईदुनिया ब्यूरो, देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाऊवाला में तीज उत्सव के अवसर पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और उनकी अपेक्षाएं व सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति राज्य की वास्तविक शक्ति है। राज्य निर्माण के संघर्ष से लेकर विकास यात्रा तक महिलाओं की भूमिका प्रेरणादायी रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों, कृषि, बागवानी, होमस्टे और उद्यमिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने के साथ उन्हें निर्णय लेने की शक्ति और नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2.65 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं को रोजगार और आधुनिक अवसरों से जोड़ने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज, ड्रोन दीदी, सोलर सखी और महिला सारथी जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 'सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड' के विजन को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 को

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु सरकार ने याचिका में कर्नाटक को 15 दिनों तक रोजाना 3,500 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि कर्नाटक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने 30 जुलाई को कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि कर्नाटक ने इस निर्देश के अनुसार पानी नहीं छोड़ा है। राज्य ने 15 दिनों की अवधि में कुल 4.536 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग की है।

नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड का धामी ने किया निरीक्षण

नईदुनिया ब्यूरो, देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाऊवाला में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम से लौटते समय प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पुनर्निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्थाओं और यातायात संचालन की स्थिति का जायजा लिया तथा अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने युद्धस्तर पर काम करते हुए महज 12 घंटे में एप्रोच रोड का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया। इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था जल्द सामान्य हो गई और लोगों को राहत मिली। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं और कार्मिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में आमजन की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

असम-अरुणाचल सीमा पर फायरिंग, 8 ग्रामीण घायल

▸▸ अतिक्रमण को लेकर विवाद के बीच मिंगमांग बस्ती में हुई घटना, सात गंभीर

नईदुनिया ब्यूरो, धेमाजीः असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सोमवार सुबह फायरिंग की घटना सामने आई। अरुणाचल प्रदेश की ओर से आए अज्ञात बदमाशों ने असम के धेमाजी जिले में स्थित मिंगमांग बदती अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में गोलीबारी कर दी। घटना में असम के आठ ग्रामीण घायल हो गए। इनमें सात की हालत गंभीर बताई गई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, फायरिंग की घटना सुबह सीमा क्षेत्र में स्थित मिंगमांग बस्ती में हुई। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद सीमा क्षेत्र में स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। हालांकि, फायरिंग करने वाले लोगों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना में घायल हुए आठ ग्रामीणों में सात की स्थिति गंभीर बताई गई है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, घटना मिंगमांग बस्ती के आसपास हुई। सीमा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों की ओर से की गई गोलीबारी में ग्रामीणों के घायल होने के बाद प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

फायरिंग की घटना के पीछे अतिक्रमण को लेकर विवाद बताया जा रहा है। हालांकि, घटना के अन्य कारणों और फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। सोमवार सुबह हुई इस घटना में आठ ग्रामीणों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि सात गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं।

जंग लंबी खिंचने के बीच अमेरिका का फोकस बदला

परमाणु समझौते के बिना भी जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप

▸▸ ईरान ने सैनिक वापसी और प्रतिबंध हटाने की मांग रखी

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ औपचारिक परमाणु समझौते के बिना भी मौजूदा संघर्ष खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की प्रमुख शर्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलना है। ईरान अगर इस मार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है तो अमेरिका संघर्ष से पीछे हटने पर विचार कर सकता है। ट्रंप ने यह विकल्प अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा है।

पहले अमेरिका की प्राथमिकता ईरान के साथ नया परमाणु समझौता करना थी। हालांकि, संघर्ष लंबा खिंचने के बाद अमेरिकी रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इसलिए इसके खुलने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम हो सकता है। ईरान ने होर्मुज खोलने के बदले अपनी शर्तें रखी हैं। इनमें युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना, समुद्री नाकाबंदी हटाना, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाना, विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्ति लौटाना और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है। ईरान ने अपने सहयोगी सशस्त्र समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग भी की है। अमेरिका में भी लंबे संघर्ष को लेकर दबाव बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पेट्रोल और रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ सकता है। अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले यह ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। ट्रंप पहले भी संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है।

ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं। उनका यह भी मानना है कि ईरान दोबारा परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश करता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में औपचारिक परमाणु समझौते की तुलना में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना तत्काल प्राथमिकता बनता दिख रहा है। ईरान की सैन्य क्षमता भी अमेरिका के लिए चुनौती बनी हुई है। युद्ध से पहले उसके पास तीन हजार से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें होने का आकलन था। उसके पास बड़ी संख्या में ड्रोन भी हैं। पश्चिम एशिया में हिजबुल्लाह, हूती और इराक के कुछ सशस्त्र गुटों के साथ उसके संबंध भी हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसका सबसे संकरा हिस्सा करीब 39 किलोमीटर चौड़ा है। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद अहम है। इसलिए इसके नियंत्रण और सुरक्षित आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद संघर्ष खत्म करने की राह में बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय राजदूत से की पहली मुलाकात

काठमांडू, एजेंसीः नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सोमवार को भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से वन-टू-वन मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी विदेशी राजदूत के साथ शाह की यह पहली अकेली बैठक है। श्रीवास्तव ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और भारत की ओर से नेपाल के साथ संबंधों व सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों के बीच भारत-नेपाल संबंधों, विकास सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

शाह ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध पुराने और भरोसेमंद हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तथा बिजली, सड़क और अन्य विकास कार्यों में सहयोग जारी रखने पर जोर दिया।

शाह ने सोमवार को चीनी राजदूत झांग माओमिंग से भी मुलाकात की। दोनों के बीच नेपाल-चीन संबंधों, आपसी हित और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद शाह ने विदेशी राजदूतों के साथ समूह में बैठक करने की नीति अपनाई थी। वह विदेश मंत्री के स्तर से नीचे के विदेशी अधिकारियों से वन-टू-वन मुलाकात नहीं करते थे। अब सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सलाहकारों की राय के बाद शाह ने नेताओं, कारोबारियों और उद्योगपतियों के साथ भी व्यक्तिगत बैठकें शुरू की हैं।

परीक्षा धांधली के विरोध में छात्रों का विस मार्च

बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ी; कई छात्र घायल

नईदुनिया ब्यूरो, रांचीः जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च किया। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा गेट के पास पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प की स्थिति बनी। पुलिस ने दो-तीन बार लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ छात्रों के सिर पर चोटें आने की जानकारी है।

आंदोलनकारी सुबह करीब 10 बजे पुरानी विधानसभा के पास एकत्रित हुए और वहां से विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए। पुलिस ने विधानसभा के आसपास कंटीले तारों समेत छह स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की थी। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी।

पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने के बाद कुछ छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें भी फेंकीं। कुछ छात्रों ने मौके पर राष्ट्रगान भी गाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को गलत बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार से छात्रों की समस्याएं सुनकर उनका तत्काल समाधान करने की मांग की। छात्र पिछले 17 दिनों से जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्रनाथ महतो समेत छह छात्र भूख हड़ताल पर हैं और वे एंबुलेंस से विधानसभा घेराव में पहुंचे। इधर, सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। 21 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय में छापे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था।

कोर्ट ने अभिषेक को दी विदेश में इलाज की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने और अपनी पसंद के उपचार का विकल्प चुनने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें विदेश जाकर इलाज कराने से संबंधित प्रतिबंध में राहत देने से इनकार किया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाकर उपचार कराने की अनुमति प्रदान की।

उत्तरकाशी में 4.2 तीव्रता का भूकंप कई इलाकों में महसूस हुए झटके

नईदुनिया ब्यूरो, उत्तरकाशीः उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार देर रात 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके रात 1 बजकर 21 मिनट पर महसूस हुए। अधिकारियों के अनुसार, अब तक भूकंप के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

भूकंप का केंद्र बड़कोट तहसील के राजगढ़ी इलाके के पास बताया गया है। इसकी गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे थी। कम गहराई में भूकंप का केंद्र होने के कारण आसपास के कई क्षेत्रों में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी के अलावा बड़कोट, पुरोला, मोरी, चिन्यालीसौड़ और डुंडा सहित यमुना घाटी के कई इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। अचानक धरती में कंपन महसूस होने के बाद कई लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद अभी तक किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में अधिकारियों और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जंतर-मंतर का विवादित बयान, यूट्यूबर गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, कोच्चिः केरल पुलिस ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर विवादित बयान देने के आरोप में यूट्यूबर टीजी मोहनदास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के लिए उनके डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, मोहनदास ने 24 और 25 जुलाई को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किए थे। आरोप है कि वीडियो में उन्होंने जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों पर कर्फ्यू लगाने और प्रदर्शन समाप्त नहीं करने पर फायरिंग का आदेश देने जैसी बातें कही थीं। मोहनदास भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं।

धार्मिक शिक्षा संस्थानों की निगरानी संबंधी मांग खारिज

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों की निगरानी और नियमित निरीक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे संस्थानों का पंजीकरण, मान्यता, निगरानी और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। अदालत की ओर से सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने और इस मामले को उचित मंच के समक्ष रखने की अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने धार्मिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों को लेकर अपनी दलील रखी। याचिका में ऐसे संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनके संचालन से जुड़े नियमों को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों का पंजीकरण और मान्यता सुनिश्चित की जाए।

चुनौती *नवंबर में मतदान, कांग्रेस का बहुमत खोने पर ट्रंप को डेमोक्रेट्स के साथ करना होगा तालमेल...*

मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की ताकत दांव पर, रिपब्लिकन पार्टी के सामने मुश्किल

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इप्सोस-एएपीआई सर्वे के मुताबिक, चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65 प्रतिशत तक है। मिडटर्म चुनाव ट्रंप के चार साल के कार्यकाल के बीच होने वाला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है। इसमें कांग्रेस के साथ राज्यों और स्थानीय सरकारों के कई अहम पदों के लिए मतदान होगा।

अगर रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में बहुमत खो देती है तो ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, लेकिन उनके फैसलों पर रोक-टोक बढ़ सकती है। टैरिफ, वीजा और इमिग्रेशन से जुड़े फैसलों को लागू करने में उन्हें डेमोक्रेट्स के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कार्यकाल के बाकी दो वर्षों में ट्रंप को कांग्रेस के साथ अधिक तालमेल बनाकर चलना होगा। महँगाई ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। इप्सोस सर्वे में 54 प्रतिशत लोगों ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को मतदान का प्रमुख मुद्दा बताया। एपी-एनओआरसी सर्वे में केवल 32 प्रतिशत लोगों ने माना कि ट्रंप अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह संभाल रहे हैं। वहीं 69 प्रतिशत अमेरिकियों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को खराब बताया। 65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि रोजमर्रा का किराना महंगा हो रहा है।

इमिग्रेशन नीति को लेकर भी ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे में 61 प्रतिशत अमेरिकियों ने उनकी इमिग्रेशन नीति का विरोध किया, जबकि 39 प्रतिशत ने समर्थन किया। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में इस नीति को 49 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला था।

ईरान युद्ध भी चुनाव में अहम मुद्दा बन रहा है। 20 प्रतिशत मतदाताओं ने इसे मतदान का प्रमुख मुद्दा बताया। युद्ध लंबा खिंचने और तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका है। रिपब्लिकन पार्टी के दोनों सदनों में बहुमत खोने पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना भी बढ़ सकती है। कांग्रेस के पास टैरिफ, इमिग्रेशन, सैन्य कार्रवाई और बजट से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण अधिकार हैं। अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का बंटवारा चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे में कांग्रेस में बहुमत का बदलना ट्रंप की नीतियों और फैसलों पर सीधा असर डाल सकता है।